MR. CHAIRMAN: But we are discussing the Telugu-Ganga.

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH: Yes, it is part of this, Sir. These two projects, which are very old projects, plus six medium projects all dealing with the Krishna Basin area with regard to surplus water be given to us, are pending clearance by the Central Government. I would like to know from the honourable Minister as to when clearance is going to be given to the State of Maharashtra for these two major projects and six medium projects.

SHRI B. SHANKARANAND: Sir, we were talking about Telugu-Ganga but he is talking about... (*Interruptions*) ...

MR. CHAIRMAN: The honourable Member's point is that these rivers are *in the same basin* (*Interruptions*) ...

SHRI VISHVAJIT PRITHVIJIT SINGH: If it is inconvenient now, he can give it later.

MR. CHAIRMAN: I am coming to your help.

SHRI B. SHANKARANAND: I am not going to assure that which I am not able to do. Sir, the boundaries of the drought-prone areas are no respecters of the political boundaries of the States in this country. There are drought-prone areas on the side of Andhra Pradesh, Karnataka and Maharashtra... (*Interruptions*)... I do not think there is a drought-prone area in this House. We are interested in clearing the project including the projects referred to by the honourable Member—the two major projects of Maharashtra—but they have not been held up for anything except techno-economic viability reasons which are the basic considerations for clearance of any project.

*62. [*The questioner* (*Dr. Shyam Sundar Mohapatra*) *was absent. For answer* vide *Cols.* 30-31 Infra]

"हुडको" द्वारा भवनों का निर्माण

*63. **श्री हुक्मदेव नारायण यादव** : क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "हुडको" द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कहां-कहां पर कितने भवन बनाये गए हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि "हुडको" द्वारा बनाये गए भवनों के घटिया निर्माण के सम्बन्ध में कोई जांच की गयी थी ; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

शहरी विकास मंत्री (श्री अब्दुल गफूर) : (क) हुडको मूल रूप से धन की व्यवस्था करने वाला संस्थान है तथा यह निर्माण कार्य नहीं करता है । तथापि, इस अवधि के दौरान, हुडको द्वारा एम.बी. रोड सेक्टर सात, नई दिल्ली में 875 क्वार्टरों का निर्माण कर रहा था ।

(ख) मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन के अधिकारियों ने निर्माण कार्यों की जांच की थी ।

(ग) मुख्य तकनीकी परीक्षक (सी.टी.ई.) ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस पर हुडको में आवश्यक कार्यवाही के लिए जांच की जा रही है ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, उत्तर में मंत्री महोदय ने यह कहा कि तथापि इस अवधि के दौरान मैं उस अवधि को जानना चाहता हूं कि वह अवधि क्या है यानी कब से कब तक के बीच ? दूसरी जांच कब हुई और जांच करने वालों ने अपना प्रतिवेदन कब समाप्त किया और हुडको द्वारा इस प्रतिवेदन पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और यदि नहीं तो कब तक कार्रवाई की जायेगी ?

श्री अब्दुल गफूर : जैसा मैंने पहले कहा है यह हुडको कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करता है और फाइनेंस और टेक्नीकल आफिसर्स के

जरिये से सारा काम होती है । लेकिन खास ईयर में जब जनता पार्टी की हुकूमत थी तो उनको कहा गया था कि इतना आप बनायें । जब यह बनाने के लिए काम शुरू हुआ उसके बाद कुछ टेक्नीकल एक्जामिनर्स, चीफ टेक्नीकल एग्जामिनर्स कब गये । उसमें जो बहुत सी चीजों को देखने के बाद यह पता लगा कि यह टेण्डर है, ये कांट्रक्टर्स हैं और यह एडवांस किया है ठीक नहीं है । ये सब टेक्नीकल मैटर्स रेज किये गये तो हुडको के चीफ टेक्नीकल इंजीनियर ने उस आर्गनाइजेशन से बातचीत की जिसमें बहुत सी बातें उन्होंने ड्राप कर दी । अब यह सारा मैटर सी.पी.डब्लू.डी. को दे दिया गया है । अब वह कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे । जल्दी से खत्म हो जायेगा ।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव : सभापति महोदय, मेरे तो पहले प्रश्न का उत्तर ही नहीं आया । मैंने यह प्रश्न पूछा था कि वह कमेटी जो जांच करने के लिए गई थी उसने और सी टी ई ने जांच कब शुरू की और उसने अपना प्रतिवेदन कब दिया और हुडको में वह प्रतिवेदन कार्रवाई के लिए कब से लम्बित है और अब तक कार्रवाई नहीं हुई तो इसके कारण क्या है इसका उत्तर तो आया नहीं । दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि मूल रूप से जब आपने कहा कि हुडको को निर्माण का काम करना नहीं है । यह केवल धन देने का काम करता है तो फिर यह हुडको ने फ्लैट का निर्माण कार्य दिल्ली में क्यों किया और जब दिल्ली में फ्लैट के निर्माण का काम शुरू किया है तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि खुद हुडको मकान बनाने के लिए धन देता है तब अपना ही कार्यालय किरायें के मकान में और वह भी 5 परसेंट, 10 परसेंट मार्केट रेट से अधिक पर लेकर क्यों चलाता है । दिल्ली में जब अन्य संस्थानों के द्वारा यह एजेंट बनाये जा रहे हैं तब इसने यह फ्लैट बनाने का काम क्यों शुरू किया और हुडको अधिकारियों ने, तकनीकी लोगों ने आपत्ति क्यों नहीं की और अगर उनकी आपत्ति थी तो वह क्या आपत्ति थी ?

श्री अब्दुल गफूर : सी टी ई ने 1984 में अपनी रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट के बाद से हुडको के जो चीफ टेक्नीकल एक्जामिनर है उन्होंने जाकर उन लोगों से डिसकशन की और डिसकशन करने के बाद सी टी ई ने अपनी रिपोर्ट दी । उन्होंने खुद कहा कि ये-ये प्वाईंट छोड़ दीजिए । उसके बाद जो मेन काम है कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का वह सी पी डब्लू डी को दे दिया गया है । यह काम जल्दी हो जायेगा ।

MR. CHAIRMAN: The Point which the hon. Member asked is this:

> If construction of houses is not within the charter of the HUDCO, why did it undertake construction at that time?

श्री अब्दुल गफूर : जहां तक हमको मालूम है, हुडको ने वह नहीं किया । उस वक्त की गवर्नमेंट ने कहा कि आप बनाईये, यही रिपोर्ट अभी तक मेरे पास है । हुडको कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करता है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो चीफ टेक्नीकल एक्जामिनर है वह कंस्ट्रक्शन की टेक्नीकलीटीज के संबंध में जो शिकायतें मंत्री जी के पास या गवर्नमेंट के पास आती हैं उनको देखते होंगे। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो चीफ टेक्नीकल एक्जामिनर है उसने कौन सी टेक्नीकलीटीज के संबंध में, क्वालिटी के संबंध में जांच की है, इस पर आप प्रकाश डालिये ? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बताया है कि सन् 1984 में चीफ टेक्नीकल एक्जामिनर ने अपनी रिपोर्ट दी, यह बात आपने लिखित रूप में कही है, लेकिन आप कहते हैं कि अभी भी जांच की जा रही है, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि सन् 1984 से अगर जांच जारी है और चीफ एक्जामिनर भी अपनी रिपोर्ट दे चुके हैं तो अब कौन-सी जांच की जा रही है और इस मामले में इतना विलम्ब क्यों किया जा रहा है ?

SHRI ABDUL GHAFOOR: The CTE sent its report on building works and the works on internal sanitation, water supply raising various points on the award of works contract, contract clauses, interpretation of contract agreement clauses, including those on

part rates and secured advances, quality of construction, quality of material and workmanship. The points were examined in consultation with the CTE oragnisation.. In the process some of the points raised above have been dropped by the CTE itself. Since the matter involved is of technical nature and in the light of the discussion with the CTE Organisation, a Technical Officer of the rank of Chief of the HUDCO has been appointed to investigate the various points raised by the CTE. the investigation by the Technical Officer is in progress.

MR. CHAIRMAN : The point asked by the Member is that it has been kept for examination for two years. When the examination is going to be over?

श्री अब्दुल गफूर : जल्दी हो जाएगा ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : माननीय मंत्री ने कहा कि हुडको का काम मकान बनाना नहीं है, धनराशि देना है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हुडको किस-किस को धनराशि देता है ? क्या उसमें प्राइवेट बिल्डर्स और प्राइवेट कंट्रेक्टर्स का भी समावेश होता है ? आप उनको कितना परसेन्टेज देते हैं और किन-किन शर्तों पर देते हैं ?

श्री अब्दुल गफूर : यह तो बहुत पुरानी चीज है कि हुडको क्या करता है और किस को लोन देता है । यह क्वेश्चन इस हाउस में कई दफा आ चुका है । यह लो इनकम ग्रुप, हाउसिंग कोआपरेटिव सोसायटीज वगैरह को लोन देता है ।

श्री शंकर सिंह वाघेला : प्राइवेट बिल्डर्स को देता है या नहीं ? . . . (**व्यवधान**) ।

I want to know whether HUDCO is giving loan to private builders and private contractors. if so, under which conditons has it been giving?

MR. CHAIRMAN : The Minister wants a notice for this.

श्री प्यारे लाल खंडेलवाल : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने कहा कि हुडको देश भर में मकान बनाने के लिए विभिन्न संस्थाओं को धन देता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि हुडको जो यह धन देता है उसके जरिए से जो मकान बनाये जाते हैं उनके संबंध में क्या सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि हुडको द्वारा धन देने पर जो मकान बनाये जाते हैं उनके क्वालिटी कंट्रोल को देखने के लिए क्या आप इंडिपेन्डेन्ट मशीनरी तैयार कर रहे हैं जिससे यह देखा जा सके कि जो खराब सीमेंट लगाया जाता है, ईंटें खराब लगाई जाती हैं उसका पता लग सके?

श्री अब्दुल गफूर : मैंने इसका जवाब पहले ही दे दिया है कि हुडको कंस्ट्रक्शन का काम खुद नहीं करता है । जो टेक्नीकल चीजें होती हैं, जो रिसर्च का काम होता है, वह हुडको देता है । जब कोई उनसे पूछता है तो उनकी वह सब चीजें बताते हैं ।

श्री प्यारेलाल खंडेलवाल : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब हुडको धन देता है तो मकानों की क्वालिटी कंट्रोल के लिए वह कोई मशीनरी डेवलप करने पर विचार रहा है ?

श्री अब्दुल गफूर : खराब रहती है मशीनरी, हर जगह होती है । हुडको के अधिकारी जाते हैं और देखते हैं । हुडको जो रुपया देता है, हिन्दुस्तान के अंदर पहली प्रायरिटी उन लोगों को होती है । जो कोआपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं और जो कांट्रेक्टर के जरिये मकान बनाते हैं । ये सारी चीजें बहुत दिनों से चल रही हैं ।

श्री रामचन्द्र विकल : मान्यवर, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें से कुछ प्वाइंट निकाल दिये गये हैं । ये जो प्वाइंट निकाले गये हैं वे कौन-कौन से प्वाइंट निकाले गये हैं और क्यों निकाले गये हैं, इसको मंत्री जी स्पष्ट करें ?

श्री अब्दुल गफूर : ये सारी चीजें मेरे पास नहीं हैं । जितना पूछियेगा सब चीजों को मंगाकर आप को दे दूंगा । प्वाइंट का मतलब यह है और माननीय मेम्बर के दिमाग में यह बात है कि मकान बनाने में क्या क्या खराबियां उन लोगों ने पायी । तो उस मकान

की बर्कम्नेशिप कैसी थी तो उसमें मेन प्वाइट टेक्नीकल था कि आपने यह जो कान्ट्रेक्ट दिया बनाने के लिये, पानी के पाइप जो लगे यह जो दूसरे काम थे उसमें आपने कितना एडवांस दिया और इन सब चीजों को देखने के लिये हुडको के टेक्नीकल आफिसर्स ने उनसे क्या कहा यह मैंने आपको बढ़कर बताया कि कम से कम 10-12 प्वाइट हैं। बाद में उन लोगों ने...

श्री रामचन्द्र विकल : जो प्वाइंट निकाले गये वे कौन से थे और वे क्यों निकाले गये यह आप बता दें ?

SHRI ABDUL GHAFOOR : Sir, at a number of places CIGI pipes were out of plumb. Even GICI pipes were also out of plumb. Some are being put in plumb....*(interruptions)*

MR. CHAIRMAN : I think I will go to the next Question. Now, Question No. 64.

Drinking water projects in Karnataka

*64. SHRI F. M. KHAN: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) what are the projects undertaken or likely to be undertaken by the Central Government to solve the problem of drinking water in Karnataka and what are the details of the expenditure likely to be incurred on each project;

(b) by when, these projects are likely to start functioning; and

(c) what are the main difficulties, if any ,in the implementation of the projects?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BUTA SINGH): (a) to (c) A statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

Provision of drinking water is the responsibility of the States. The Central Government assists the States in their efforts in providing drinking water in rural areas through asistance under the Accelerated Rural Water Supply Programme. For the Seventh Paln Karnataka has an outlay of Rs. 75.00 crores under the State Sector Minimum Needs Programme (MNP). Under the Central Sector ARWSP an amount of Rs. 15.66 crores was provided to Karnataka during 1985-86. The provisonal ARWS allocation for Karnataka for 1986-87 is Rs. 12.54 crores and an amount of Rs. 6.27 crores has already been released to the State as first instalment.

In addition a ceiling of expenditure of Rs. 31.01 crores has been approved under drought relief for drinking water schemes during 1985-86, including spill-over for 1986-87.

The State Govenment formualtes and implements schemes for providing drinking water facilities under the State Sector MNP, drought relief and the Central Sector ARWSP. Only in the case of schemes under ARWSP prior technical approval of the Central Government is obtained.

SHRI F. M. KHAN : Sir, I would like to know how many memoranda have been received by the Centre from the State Governmnet seeking Central assistance to enable it to take up adequate relief measures in the affected areas of the State. What are the details of various relief programmes in the districts for which assistance was sought? What are the details of Central assistance provided to the State so far? Whether the Government is aware that the shortage of drinking water is a perennial problem in the urban and rural areas of Karnataka State? So much so that this time the city of Bangalore has also been effected. Therefore a number of cities and villages in the State which are facing drinking water problem Whether the Government is aware that many drinking water schemes remain bagged down in red-tape as a result of which these are delayed for a long time adding to the woes of the village population?